दिनांक:14.12.2014

प्रधानमंत्री को ज्ञापन

बीएसएनएल बचाओ – भारत बचाओ

सेवा में

श्री नरेंद्र मोदी,

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी,

नई दिल्ली – 110001

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

हम, इस देश के लोग, भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल), दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2000 में निर्मित किया गया था, की वर्तमान वित्तीय स्थिति और सेवाओं के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। हममें से अधिकांश निगमीकरण से पहले, दूरसंचार विभाग की दूरसंचार सेवा के प्रयोक्ता रहे हैं और अभी भी बीएसएनएल के साथ जुड़े हुए हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, हम जानते हैं कि बीएसएनएल की बाज़ार हिस्सेदारी में लगभग 10 प्रतिशत तक की गिरावट हुई है, साथ ही इनकी सेवाएं पहले की तरह प्रभावी नहीं रही हैं और इस दिशा में इनका विकास और विस्तार उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पर होना चाहिए। बीएसएनएल की सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ इसका विकास और विस्तार किए जाने की तुरंत आवश्यकता है।

हम जानते हैं कि बीएसएनएल वर्ष 2009-10 के बाद से गत चार वर्षों के दौरान लगभग 28,000 करोड़ रु0 की संचित हानि के साथ घाटे में चल रहा है, यद्यपि पहले के नौ वर्षों के दौरान यह 48,000 करोड़ रु0 के सचयी लाभ के साथ अच्छा लाभ कमा रहा था। हमें सूचना मिली है कि बीएसएनएल सरकार की वर्तमान नव-उदारवादी नीतियों, जो कि उनकी अपनी कंपनी बीएसएनएल की बजाय निजी कंपनियों के पक्ष में है, के कारण कमजोर हो रहा है। आश्वासन जैसे कि बीएसएनएल को एडीसी का भुगतान करना, दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल द्वारा भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु बीएसएनएल को हुई हानि के लिए यूएसओ निधि, सरकार के सार्वभौमिक सेवा दायित्व के भाग के रूप में, के माध्यम से उदार अनुदान, को बिना किसी औचित्य के समाप्त कर दिए जाने के कारण बीएसएनएल को भारी नुकसान हुआ है। इस संबंध में हमारी सुदृढ राय है कि बीएसएनएल को दी जाने वाली इन सहायताओं को बहाल किया जाए और इन आश्वासनों को सम्मान दिया जाए।

सेवाओं के पतन का मुख्य कारण मोबाइल, ब्रॉडबैंड मोडम, ड्रॉप वायर, टेलीफोन उपस्कर, केबल इत्यादि जैसे उपस्करों की कमी होना है जिसके कारण ये सेवाएं बुरी तरह और प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। जब बीएसएनएल के पास मोबाइल उपस्कर के प्रापण हेतु पर्याप्त धनराशि और अंतिम रूप में दी गई निविदाएं थीं, जिसकी वर्ष 2006 में तत्काल आवश्यकता थी, उस समय इसे सरकार के आग्रह पर निजी कंपनियों के पक्ष में तीन बार रद्द कर दिया गया था। यदि उन निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया होता और उपस्करों को खरीद लिया गया होता तो बीएसएनएल दूरसंचार क्षेत्र में प्रथम स्थान पर होता। कम से कम अब, सरकार को बीएसएनएल को राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिससे यह टावरों सहित अपेक्षित उपस्करों को खरीदने में सक्षम हो जाएगा और इसकी सेवा-गुणवत्ता में सुधार होगा।

बीएसएनएल के माध्यम से अन्य कंपनियों जैसे कि टावर कंपनी इत्यादि के प्रस्तावित गठन का परिणाम केवल विघटन होगा अतः इसे बंद कर देना चाहिए। एमटीएनएल, 20,000 करोड़ रू0 के भारी कर्ज में डूबी कंपनी, के साथ बीएसएनएल के विलयन का प्रस्ताव, बीसएनएल के पुनरूद्धार में बड़ी बाधा उत्पन्न करेगा।

इस परिस्थिति के तहत, हमारा अनुरोध है कि बीएसएनएल का पुनरूद्धार करने और इसे सशक्त बनाने तथा लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्काल निम्नलिखित कार्रवाई की जाए:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 2 बीएसएनएल निदेशकों के पदों, जो कई महीनों से खाली पड़े हैं, को तत्काल भरा जाए।
2. सहायक टावर कंपनी के निर्माण को रोकना । बीबीएनएल को बीएसएनएल के साथ विलयित किया जाए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में घाटा उठाने वाले लैंडलाइन कनेक्शनों की प्रतिपूर्ति करने हेतु बीएसएनएल को पर्याप्त मुआवज़ा प्रदान किया जाए।
4. बेहतर सेवा के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने पर अधिक ध्यान देते हुए विकास, विस्तार हेतु उपस्कर का प्रापण और पारेषण नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए और अधिक टावरों की स्थापना की जाए।
5. दूरसंचार विभाग से बीएसएनएल को परिसंपत्तियों का अंतरण किया जाए।
6. बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलयन के प्रस्ताव को समाप्त किया जाए ।
7. बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम का निःशुल्क आवंटन किया जाए ।
8. नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बीएसएनएल को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।
9. बीएसएनएल 4जी सेवाएं उपलब्ध कराए।
10. बीएसएनएलएल द्वारा अभ्यर्पित किए गए स्पेक्ट्रम के लिए सराकार द्वारा बीएसएनएल को 6,000 करोड़ रू0 के बीडब्ल्यू स्पेक्ट्रम प्रभारों को लौटाया जाए ।
11. कर्मचारियों की नई भर्ती की जाए ।

12. केंद्रीय / राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए बीएसएनएल की सेवा अनिवार्य हो । हमारा पुनः अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस संबंध में पर्याप्त आवश्यक कार्रवाई करें ताकि सार्वजनिक क्षेत्र दूरसंचार कंपनी, बीएसएनएल का पुनरुद्धार किया जा सके और लोगों को पहले की तरह बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें ।

प्रार्थी :-

सं0	नाम	स्टेशन	हस्ताक्षर